ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
Question No. 182—contd.

I think, we should move to another question ...(*Interruptions*)...

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, you said that you will give me an opportunity ...(*Interruptions*)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, you have not given me an opportunity in the first and the second questions. I am deprived of totally ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will give you in the third question. My observation is, the question should be pointed. This is the rule. This question does not come within the rules. You cannot discuss a policy matter in the Question Hour. There has to be a separate discussion on the entire Transport Policy and the condition of the roads now ...(*Interruptions*)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, I want to ask about the implementation of the policy ...(*Interruptions*)...

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, let us have a half-an-hour discussion on this so that everything will be clarified ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I agree because of the nice suggestions made by Mr. Chavan from Mahrashtra, hon. Members from North-East and hon. Members from other parts of the country.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, if we have an half-an-hour discussion, every Member would get an opportunity to speak on this subject.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think it is a very serious matter.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: It is a very serious matter, Madam. Maharashtra is agitating to have the service charges increased. Therefore, it would be advisable ...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us discuss this for half-an-hour, one hour, two hours. But now let us go to the next question.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Thank you very much, Madam.

Asian Development Bank Loan for Providing Telephones in Rural Areas

*183. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Asian Development Bank has approved loan of Rs. 400 crores for providing telephones in rural areas in India;

(b) if so, the conditionalities attached with the grant of this loan; and

(c) the details of utilization of this loan in the eastern parts of U.P.?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी हां। भारत द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण दूरसंचार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल ने हाल ही में 113 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 400 करोड़ रु०) का ऋण मंजूर किया है।

(ख) वह ऋण एशियाई विकास बैंक की मानक शर्तों पर प्राप्त किया गया है। ऋण भुगतान की अवधि 24 वर्ष है जिसमें चार वर्ष की ग्रेस अवधि भी शामिल है।

(ग) इस ऋण से उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल के 42 जिलों के लगभग 31,788 गावों को एक-एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किया जाएगा। उन जिलों का ब्यौरा जिन्हें टेलीफोन दिए जाने हैं, विवरण में दिया गया है।

विवरण

एशियाई विकास बैंक ऋण के सहयोग से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने वाले उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल के जिलों के ब्यौरे

क्रम सं०	जिलों के नाम	क्रम सं०	जिलों के नाम
1.	अम्बेडकर नगर	22.	झांसी
2.	इलाहाबाद	23.	कानपुर
3.	आजमगढ़	24.	कानपुर देहात
4.	बलिया	25.	लखीमपुर
5.	बांदा	26.	ललितपुर
6.	बाराबंकी	27.	लखनऊ
7.	बस्ती	28.	महाराजगंज
8.	बहराइच	29.	मैनपुरी
9.	भदोही	30.	मऊनाथ भंजन
10.	देवरिया	31.	महोबा
11.	इटावा	32.	मिर्जापुर
12.	फिरोजाबाद	33.	प्रतापगढ़
13.	फरूखाबाद	34.	पतरेना
14.	फतेहपुर	35.	रायबरेली
15.	गाजीपुर	36.	शाहजहांपुर
16.	गोण्डा	37.	सिद्धार्थ नगर
17.	गोरखपुर	38.	सीतापुर
18.	हमीरपुर	39.	सौनभद्र
19.	हरदोई	40.	सुलतानपुर
20.	जालौन	41.	उन्नाव
21.	जौनपुर	42.	वाराणसी

SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Madam, I had asked about the conditionalities in regard to this loan from the ADB. The answer given is that these are standard conditions.

What I would like to say here is that these conditionalities have been tailor-made by an Australian consultant who did not even visit Eastern U.P. He came here in May and June when the temperature was 45 degrees. He stayed in a Delhi hotel. He did not associate any Indian entrepreneurs who have made great strides in this field in the last three years.

The conditions imposed are such that they favour, on the technical side, only the U.S. and European companies. I would like the hon. Minister to confirm this—the position in regard to the conditionalities. One of the conditions is that only those Indian companies which have an average turnover of Rs. 150 crores in the last three years can participate in the tender.

Madam, this industry is just three years old. Developments have taken place only in the last three years.

THE DEPUTY CHAIRMAN: please put your question you have another question also.

SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: It is part of the same question, Madam. My question is: why ae the Indian companies which have made great strides in this field not allowed to participate in the tender?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: उपसभापति महोदया, यह प्रस्ताव 1993 से चला आ रहा है और अब करीब-करीब यह फाइनल पोजिशन में पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के जो 42 जिले हैं उनके लिए इसको चुना गया है। 400 करोड़ रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जायेगा और 200 करोड़ रुपया विभाग लगायेगा। महोदया, माननीय सदस्यों को यह भी मालूम है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में हमारे देश का भी सहयोग है। हम इसके सदस्य हैं। यह बैंक विकसित और विकासशील देशों को ज्यादातर ऋण पर पैसा देता है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: आपने सवाल ही नहीं समझा है।...(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: आपका सवाल है कि डोमेस्टिक कम्पनियों के लिए शर्त लगाई गई है कि कितना टर्न ओवर हो तभी इनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जायेगा। मैडम, जो एमएआरआर की हमारे देश में पोजिशन है वह सब लोगों को विदित है। यह नई टेक्नोलॉजी होगी। हमारे एन्टीना से आईएसडी, एसटीडी की सुविधा भी रहेगी और जो इसके टेंडर जारी किये गये हैं उसमें इंडियन कम्पनियों ने भी टेंडर फार्म खरीदे हैं। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। कुछ टर्न आवर की सुविधा पर शर्त लगाना इसलिये

भी जरूरी था कि फर्जी कम्पनियां बनाकर उसमें पार्टिशिपेट न करें। इसमें 140 करोड़ टर्न ओवर हो, यह शर्त रखी गई।

SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Madam, the estimated price, per subscriber, of this imported equipment which would come from the U.S.A. and Europe,—would be Rs. 1-3 lakhs per subscriber. There is no condition of technology transfer. Indian companies can give some service for Rs. 25,000. They might have got the tender but the condition, as I said earlier, is that they should have an average turnover of Rs. 150 crores, which none of them will be able to satisfy. This is a national condition, so they will not be able to supply. Then, shall we buy from abroad under the pretext of aid? It is not an aid, it is a loan. And a loan has to be repaid—there is no free lunch. If the loan has to be repaid even in 20 years, then why should we pay Rs. 1 lakh, two lakhs or three lakhs per subscriber? That is the second part of my first question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, this is not the second part of your first question. This is the second supplementary. We do not have such a system, I am sorry, I have to inform you. There are other Members also who have a right to ask supplementaries.

SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Let me finish this, at least.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer first.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: इसमें कोई नयी शर्त नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक की टेंडर की कंडीशंस होती हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, लोन लेने के पहले मानना पड़ता है। यह कोई नया लोन नहीं है। एशियन डवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से तमाम परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार लोन लेती रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश खास तौर से टेलीफोन के संबंध में नेशनल एवरेज से बहुत पिछड़ा हुआ है। 1993 से यह प्रस्ताव चल रहा है। अभी अन्तिम चरण में है। यह हम को भी फीड बैक मिला था कि इसमें जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, वह हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हमने थोड़ी-बहुत जानकारी की लेकिन जो टेंडर फार्म हैं इस समय मिल रहे हैं, उसमें डोमेस्टिक कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। जो डोमेस्टिक कंपनियों में एम०आर०आर० के बारे में या उनकी लोकेशन के बारे में जो कंडीशंस हैं उनके बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। इसमें आई०एस०डी० और एस०टी०डी० सुविधा गांव के लोगों को भी मिल जाएगी। हम समझते हैं कि इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलना चाहिये। (व्यवधान) यह ट्रायल बेसेज पर है पूर्वी उत्तर प्रदेश में (व्यवधान) यह ट्रायल बेसेज पर है (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Malkaniji, let me hear. You may not be interested, but I am interested.

SHRI K.R. MALKANI: We are also interested.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then let him speak. ..(*Interruptions*).. This is not the way. Please keep quiet.

SHRI K.R. MALKANI: This is not a classroom. ..(*Interruptions*)...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, वह लोग तो राजनीतिक भावना से करेंगे। (व्यवधान) हम समाजवादी पार्टी के हैं। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इंटरप्ट करेंगे (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल: यह बात गलत है (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहेबा, सीधी बात यह है... (व्यवधान)

श्री एस०एस० अहलुवालिया: इसमें पार्टी का सवाल कहां से आ गया? आप भारत सरकार के मंत्री हैं (व्यवधान) आप समाजवादी पार्टी के संचार मंत्री नहीं है (व्यवधान) यहां पर पार्टी का नाम मत लाइये (व्यवधान)

उपसभापति: मंत्री जी, कोई भी सरकार हो, वह सरकार होती है। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन आप भी हमारा सहयोग कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त: एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका सीधा जवाब दें (व्यवधान)

श्री एस०एस० अहलुवालिया: कोई पार्टी का

सदस्य सवाल नहीं पूछता है (**व्यवधान**) इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है (**व्यवधान**)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: हम आपका पूरा आदर करते हैं और आप पूरा सहयोग भी कर रहे हैं (**व्यवधान**) वह लोग उत्तर देने में बाधा डाल रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: कोई बाधा नहीं डाल रहा है (**व्यवधान**)। हम सवाल पूछना चाहते हैं और यह कहते हैं कि बाधा डाल रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं देते हैं और हम को लेक्चर देना चाहते हैं कि एशियन डवलपमेंट बैंक क्या करता है (**व्यवधान**)। यह क्या बात है (**व्यवधान**)

उपसभापति: आप बैठिये। मंत्री जी, इस हाऊस में जब सवाल किया जाता है तो वह किसी भी पार्टी से हो सकता है। जो रूलिंग पार्टी है वह भी सवाल करेगी क्योंकि मेरे पास नाम लिखे हैं। सवाल पार्टी बेसेज़ पर नहीं होते हैं। यह पार्टी मीटिंग नहीं है, यह पार्लियामेंट है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इश्युज़ के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। इसमें जो जानकारी चाहिये, अगर आपके पास जानकारी है तो आप कृपया दे दीजिये। कोई सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका सवाल न उठा कर आप सीधे-सीधे साधारण जवाब जो आपके पास है, वह आप दे दें। और भी नाम मेरे पास हैं, टाइम कम है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कि जो इण्डियन कंपनीज़ हैं उनको पार्टीसिपेट करने की इजाज़त नहीं मिल रही है, उन पर कंडीशन लगाई है। क्या यह वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक की कंडीशंस हैं या आपके मंत्रालय ने यह कंडीशंस लगाई हैं, यह सीधा सवाल है? इसीलिए मैं कहती हूं (**व्यवधान**) एक मिनट बैठिये आप, उनका जवाब आने दीजिये। अभी आप उस पर टिप्पणी नहीं कीजिये।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मैडम, उस टिप्पणी को एक्सपंज कर देना चाहिये (**व्यवधान**) Madam, the party's name should be expunged.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will see it.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, यह तो बता दें कि इंडियन टेक्नालाजी की अवेलेबिलिटी का टर्न ओवर से क्या ताल्लुक है ...(**व्यवधान**) यह तो बहुत छोटा सा सवाल है।

†उर्दू में: सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा - यह तो बता दें कि इंडियन टेक्नालाजी की अवेलेबिलिटी का टर्न ओवर से क्या ताल्लुक है ...(व्यवधान) यह तो बहुत छोटा सा सवाल है।

†उर्दू में: ओवर से क्या तालुक है - ...(व्यवधान) यह तो बहुत छोटा सा सवाल है।

उपसभापति: यही मैंने पूछा है, क्योंकि वह बहुत लम्बा क्वेश्चन होता है इसलिए वे कन्फ्यूज हो जाते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मान्यवर, 40 मिलियन डालर का वार्षिक कारोबार इसलिए रखा गया है स्पेशल ताकि फर्म निविदा शर्तों के अनुसार उपकरण सप्लाई करने की स्थिति में हों। अगर उसकी टर्न ओवर ही नहीं होगी तो वह सप्लाई क्या करेगी। इसलिए टर्न ओवर की शर्त इसमें लगायी गयी है कि 40 मिलियन डालर टर्न ओवर जिस कंपनी का होगा वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है।

श्री सिकन्दर बख्त: मैंने बहुत ही मुख्तसर सवाल पूछा है। उसका सीधा साधा जवाब आना चाहिए कि इंडियन टेक्नालाजी की अवेलेबिलिटी का टर्न ओवर से क्या ताल्लुक है।

†उर्दू में: सिकन्दर बख्त: मैंने बहुत ही मुख्तसर सवाल पूछा है। उसका सीधा साधा जवाब आना चाहिए कि इंडियन टेक्नालाजी की अवेलेबिलिटी का टर्न ओवर से क्या ताल्लुक है।

उपसभापति: अवेलेबिलिटी आफ द मशीन। जवाब दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: टर्न ओवर की शर्त इसमें इसलिए लगायी गयी है कि ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं कि फर्जी कम्पनियां रजिस्टर्ड हो जाती हैं ...(**व्यवधान**) फर्जी तो ग्लोबलाइजेशन से भी हो सकती है। यह मैंने पहले बता दिया है ...(**व्यवधान**) जो फार्म अभी खरीदे गए हैं—जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टेंडर थे—उसमें इंडियन कम्पनीज ने भी फार्म खरीदे हैं ...(**व्यवधान**)

उपसभापति: श्री राम कापसे जी।

(व्यवधान)

अभी उनको पूछने दीजिए।

PROF. RAM KAPSE: Madam, my experience is that as far as the villages throughout India are concerned, most of the telephones are not in working order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In U.P.

PROF. RAM KAPSE: I want to know whether enough care has been taken when the telephones were installed in U.P. Especially when you are talking of the STD and the ISD connections, I want to know whether the PCOs will work normally.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मान्यवर, यह सही है कि हमने जब इस विभाग का कारोबार संभाला तो ग्रामीण टेलीफोनों की हालत खास तौर से बहुत खराब थी—खास तौर से एम०ए०आर०आर० की (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: आज भी है।

उपसभापति: जवाब आ रहा है। उन्होंने बोल दिया है। आप लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं ...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: यह टेलीफोन जैसे ही हो रहा है।

उपसभापति: 4-5 कनेक्शन जुड़ते हैं तो सब गड़बड़ होती है—इस हाउस में भी ...(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: प्राथमिकता के आधार पर हम ग्रामीण टेलीफोनों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं। इसकी मानीटरिंग हर वीक हमारे मंत्रालय में खुद होती है। फिर हमने लक्ष्य रखा है कि दिसम्बर के अंत तक 90 परसेंट ग्रामीण टेलीफोन बिल्कुल काम करने लगें और जनवरी के अंत तक सौ प्रतिशत का लक्ष्य हमारा है कि ग्रामीण टेलीफोन काम करें। उसके लिए आप जो भी सुझाव देंगे उनका भी हम आदर करेंगे ...(व्यवधान) पुनः असेसमेंट किया जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला: इसी सेशन में एक महीने मेरा टेलीफोन खराब रहा—एम०पी० का ...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी: इस योजना को लागू करने के पहले जो गांवों में टेलीफोन देने की योजना, इनके एक पूर्व मंत्री श्री राजेश पायलट जी ने चालू की थी और यह कहा था कि देश का कोई भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं रहेगा जो टेलीफोन से कनेक्टेड न रहे। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है और दिसम्बर जनवरी तक सब जगह टेलीफोन लग जाएंगे ...(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: लग नहीं जाएंगे ...(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी: सुधर जाएंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई सर्वेक्षण किया है कि अभी जितनी पंचायतों में टेलीफोन लगे हैं उनमें से कितने काम कर रहे हैं? हमारी अपनी जानकारी यह है कि उनमें से 95 प्रतिशत से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। सरपंचों के ऊपर अतिरिक्त भार बन गया है कि आपके इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षा कैसे करें। अगर 95 प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए आपने क्या योजना बनायी है और जो पंचायतें बच गयी हैं विशेषकर आदिवासी दूरदराज के इलाकों की पंचायतों में जहां टेलीफोन नहीं लगे हैं वहां लगाने के लिए आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और कब तक लग जाएंगे? जो लग गए हैं उनमें से कितने खराब हैं और कब तक ठीक हो जाएंगे और जो नहीं लगे हैं वे कब तक लगेंगे? ये स्पेसिफिक प्रश्न हैं, इनका स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, नई दूर संचार नीति जो थी उसमें 1997 के अंत तक सभी रेवेन्यू विलेज में, सिर्फ ग्राम पंचायतों में नहीं, ग्रामीण टेलीफोन देने की उसमें परिकल्पना की गई थी, लेकिन प्राइवेट आपरेटर्स अभी सर्विस में नहीं आए। प्राइवेट आपरेटर्स के ऊपर भी 10 परसेंट की पाबंदी थी कि वह ग्रामीण टेलीफोन देंगे। इसलिए उसमें थोड़ा विलम्ब होगा। लेकिन इस वर्ष जो हमारा लक्ष्य है 75 हजार ग्रामीण टेलीफोन देने का, अभी तक किसी भी वर्ष में ग्रामीण टेलीफोन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, 25-30

परसेंट से ज्यादा अभी नहीं लग पाए हैं। इस वर्ष हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने विभाग को निर्देश दिए हैं कि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जाए और उसके लिए बजट में अलग से 600 करोड़ रुपये का प्रावधान भी पहली बार किया गया है। महोदया, जहां तक माननीय सदस्य को यह जानकारी की आवश्यकता है कि कितने टेलीफोन ठीक काम कर रहे हैं, और कितने ठीक काम नहीं कर रहे हैं तथा वह कैसे ठीक होंगे, तो हमने वह पहले ही बता दिया कि हमने जिस वक्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था उस समय ग्रामीण टेलीफोनों की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी, आज हम थोड़ा संतोष इस पर जाहिर कर सकते हैं।

श्री अजीत जोगी: आपकी जानकारी में कितने प्रतिशत चालू हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: करीब 8 हजार से ऊपर हमारे देश में ग्रामीण टेलीफोन के बेस स्टेशन हैं और उसमें इस समय 954 खराब हैं।

श्री अजीत जोगी: यह गलत है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अगर यह गलत है तो हमको जो अधिकारियों ने सूचना दी वही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर आप यह कह रहे हैं कि यह गलत है तो खुद हम मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष में 90 फीसदी और जनवरी के आखिर तक सौ फीसदी ठीक हो जाएं।

श्री अजीत जोगी: 900 से ज्यादा केवल मध्य प्रदेश में खराब दिखा दूंगा और आप कह रहे हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में 954 खराब हैं।

उपसभापति: मंत्री जी, डिटेल अगर इनके पास है तो आप मंगाकर उसको देख लीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदया, वह जो हमको कहें वह खुद हम देखेंगे।

श्री अजीत जोगी: मैडम, मैंने इनको पत्र लिखा, मै व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। मेरे अपने गांव मे 6 माह से टेलीफोन खराब हैं। मैंने बार-बार इनको लिखा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मध्य प्रदेश उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में से है...**(व्यवधान)** फिगर हमारे पास हैं, लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा है जनवरी के अंत तक सौ फीसदी ठीक करने का उसमें हमको आपका सहयोग मिलना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि जनवरी के अंत तक हमारे सौ फीसदी ग्रामीण टेलीफोन ठीक हों...**(व्यवधान)**

उपसभापति: अभी बैठिए। ....**(व्यवधान)** नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। यह जीरो ऑवर नहीं है। अभी तो क्वश्चन आंवर चल रहा है। आप थोड़ी शांति रखिए। वह कह रहे हैं और वह मान रहे हैं।

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I concede what the Minister says, that the process of expansion of village telephones was severely affected during the last five years. In the purchase of equipment or installation process there was a total lack of transparency or such kind of things had developed. That is very true. I also agree that the Indian private industry, so far as the telecom equipment manufacturers are concerned, has not particularly come out with flying colours. But, the point is that within the Department there were properly formulated guidelines for formation of 'tender committees' for formulating tender procedures and all that. So, would the hon. Minister be kind enough to let us know how, in spite of such procedures, such violations have taken place and what are the new changes that have been incorporated so far as implementing this new scheme of purchase as part of the ADB supported approach is concerned?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदया, प्रक्रिया में जो कोई गलती होती है तो हमेशा सुधार के लिए विचार किया जाता है और टेंडर प्रक्रिया के बारे में आपने यह बहुत ही लंबा सवाल पूछ लिया। हमने उसमें कुछ गाइड लाइंस चेंज भी की हैं और निर्देश भी दिए हैं तथा उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। जैसे रिपीट ऑर्डर के नाम पर जितना टेंडर मूल होता था उससे भी ज्यादा कभी-कभी प्रचेज़ हो जाती थी। अब उसको फिक्स कर दिया गया है कि रिपीट ऑर्डर 25 परसेंट से ज्यादा नहीं होगा और वह भी इमरजेंसी में। वरन् फ्रेश टेंडर फ्लोट होगा। मैडम, एक टेंडर की जानकारी हमारे बसु जी को होगी जिस में हम को कार्टेलाइजेशन दिखायी पड़ा था। उस को हम ने कैंसिल किया और नया टेंडर जारी किया। वह ऑप्टिकल फाइबर का था। जब नया टेंडर खुला तो सिर्फ उस एक टेंडर में विभाग को 25 करोड़ रुपए की

बन्धत हुई है।

श्रीमन्, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस विभाग में पारदर्शिता रहे ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: अभी जवाब आ रहा है। टेलीफोन कनेक्शन लगने में टाइम लगता है और जब खराब हो तो धीरे लाइन जुड़ती है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: ट्रांसपेरेंसी और डवलपमेंट हमारी प्रायरिटी होगी और जो भी माननीय सदस्य का सुझाव होगा, उस का हम आदर करेंगे।

श्री नीलोतपल बसु: मैडम, मेरा यह सुझाव था ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: Let me call Mr. Yadav also.

अभी आप का जो भी सवाल था, उस का उन्होंने जो जवाब देना था, वह दे दिया है।

श्री नीलोत्पल बसु: मंत्री जी का कोई रोल नहीं होना चाहिए टेंडर में, यही मेरा सवाल है। मंत्री जी का खुद का रोल नहीं होना चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् बसु जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वह कह रहे हैं कि मंत्री जी का कोई रोल टेंडर में नहीं होना चाहिए। तो यह तो हम ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि मंत्री का काम होता है कंट्रोल सुपरविजन और कोई गलती हो तो पनिशमेंट भी देना। मैडम, हमने आते ही फैसला ले लिया है कि यह टेंडर इवैलुएशन कमेटी और आफिसर्स की जिम्मेदारी होगी कि वह टेंडर फाइनल करे और उन के फायनल करने के बाद यदि शिकायत आएगी तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन फायनलाइजेशन में हमारा कोई रोल नहीं होगा।

श्री जनार्दन यादव: मैडम, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एशियाई विकास बैंक ने जो 400 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने के लिए स्वीकृत की है, उस में बिहार का कितना हिस्सा है? उस में से बिहार के कितने गांवों में टेलीफोन लगेंगे?

उपसभापति: इस के लिए सेपरेट नोटिस दीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, इस वर्ष बिहार में साढ़े 6 हजार ग्रामीण टेलिफोन लगाने का हमारा लक्ष्य है और हम ने पहले भी कहा है कि हमारा लक्ष्य है साढ़े 6 हजार उस को हम शत-प्रतिशत पूरा करेंगे। अब यह जो लोन 400 करोड़ का है, यह सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के 42 जिलों के लिए है और यह नयी टैक्नोलॉजी है जिस की अभी एक तरह से ट्रायल होगी। फिर उस के कामयाब होने के बाद इस का और विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।

श्री मोहम्मद आज़म खान: मैडम, मंत्री जी ने अभी इस योजना के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 42 जिलों को पिछड़ा बताते हुए कहा है कि उन्हें इस का लाभ मिलेगा। तो क्या यह बिल्कुल मुतमईन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले ही पिछड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिला पिछड़ा नहीं है? अगर वहां कोई जिला पिछड़ा है और यह उन की जानकारी में है क्योंकि हम रियासत के उस पिछड़े जिले से आये हैं जहां पूरे मुल्क में कोई भी इलाका उस से ज्यादा पिछड़े और दलित लोगों का नहीं हो सकता। मैं ढाई सौ सालों तक गुलामी के पैरों तले दबे, कुचले उस शहर से यहां आया हूं जहां देखा जाये तो पूरे हिन्दुस्तान में अगर कहीं हाइएस्ट रेट आफ इलिटरेसी है तो वह रामपुर है, सब से ज्यादा अगर गरीबी कहीं है तो वह रामपुर में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नवाबों के इस शहर को पिछड़ा मान लिया जाये और उस को इस सहूलियत से वंचित न रखा जाये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् यह हम ने पहले ही कहा है कि यह ट्रायल बेसिस पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोकि सब से पिछड़ा था, वहां के लिए 400 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से हमारा 6 हजार नए टेलिफोन कनेक्शंस ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का लक्ष्य है। अब जहां तक रामपुर का सवाल है, हम और आज़म खान साहब एक साथ करीब 15—20 साल एसेंबली में रहे हैं। तो जो भी वे शिकायत और सुझाव देंगे उस का आदर करना हमारा कर्तव्य है।

उपसभापति: आप का कनेक्शन अच्छा जुड़ा है। इधर बाकी हाउस में भी जोड़ दीजिए।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam Deputy Chairman, while we are talking about telephones and assistance which is coming from the ADB or wherever else, I would request the Minister to please clarify whether the assistance that is coming is meant only for imported technology to be brought into the country or for manufacture and transfer of technology. Madam, ITI, Bangalore which has expanded all over the country was a premier institution

which was created to deal with rural communications and other requirements of the country. It played a real, if I may say so, leadership role in providing these services. Madam, it is a tragedy that today, when we mark 50 years of Independence, it has been referred to the BIFR. When our national public sector units like this are being sent to the BIFR and closed down, at the same time, we are talking about modernisation and getting assistance from all over the world to modernise rural exchanges and so on. I would like to know from the hon. Minister whether he has a commitment to reviving the existing public sector units like the ITI. I am not talking of all. But the ITI has been a premier institution in the public sector in this field. It is a pride of that department; it is a pride of the country. I, therefore, want to know from the hon. Minister whether he is prepared to make the commitment that with all the aid and assistance and the money coming, investments will be made in institutions like the ITI to revive them.

श्री दीपांकर मुखर्जी: मंत्री जी, आप बोलिएगा ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप मत दीजिए जवाब, मंत्री जी को देने दीजिए। आप क्या जवाब दे रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: आई॰टी॰आई॰ को देखा ही नहीं है उन्होंने। ...**(व्यवधान)**...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, इस मूल प्रश्न से उसका कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन आई॰टी॰आई॰ में हमारी क्षमता है और आई॰टी॰आई॰ को सप्लाई आर्डर देने में प्रायरिटी दी जाती है, जरूरत होती है तो उनको एडवांस भी हम डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं। विदेशी सहायता के लिए जो यह प्रश्न है, इसमें आई॰टी॰आई॰ का रोल नहीं है। इसमें ग्लोबल टेण्डर होगा। उसमें जो टेण्डर कंडीशन्स हैं उनके मुताबिक इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन, यह जो टेक्नोलोजी है इसके बारे में सी-डॉट से जरूर बात की जा रही है। इस टेक्नोलोजी को यहां भी डवलप किया जाएगा। अगर यह टेक्नोलोजी डवलप हो जाएगी तो आई॰टी॰आई॰ ही उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लेगी। ऐसा हम सब लोगों को पहले से विश्वास रखना चाहिए। यह टेक्नोलोजी हमारे यहां डवलप हो जाए, इसकी कोशिश की जाएगी।

उपसभापति: मिस्टर शारिक।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: क्यों आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे? इसमें इन्वेस्ट करिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: शारिक जी, बोलिए। मारग्रेट जी, इन्हें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मेडेन क्वैश्चन है यह।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैडम, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर की क्या सूरतेहाल रही पिछले 6 साल में, उससे सदन भी और ऑनेरेबिल मिनिस्टर भी वाकिफ हैं। चूंकि वहां सारा सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए उसकी तरफ खास तवज्जोह देने की जरूरत है। मैं ऑनेरेबिल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है, यहां वह कम्युनिकेशन को असर-ए-नव तरतीब और तामीर के बाद वहां कम्यूनिकेशन को कोई खास तवज्जोह दें? और, क्या मिनिस्टर साहब उनकी वजारत इस सिलसिले में कोई खास जल्द वहां चलाना चाहते हैं या उनका कोई प्रोग्राम है इस सिलसिले में?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैडम, यह प्रश्न तो सीमित था, लेकिन अब यह व्यापक हो रहा है।

श्री अजीत जोगी: ऐसा होता है राज्य सभा में। ...**(व्यवधान)**...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अभी जल्द ही हमारी जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने जो भी सुझाव दिए थे, हमने उसको मान लिया था। उनके सामने अधिकारियों को बुलाकर निर्देश भी दिए थे कि जो यह हमारे विभाग से चाहते हैं, जो भी यह टेलीफोन एक्सचेंज लगाना चाहते हैं, कुछ रिमोट एरियाज में थे, जहां बर्फ ज्यादा है वहां पर थे, हमने उसी दिन आदेश दे दिए थे कि मुख्यमंत्री जी जो सुझाव दे रहे हैं इनका तुरन्त अनुपालन किया जाए। हम इसकी समीक्षा भी कर लेंगे कि जो आदेश हमने दिए थे, उनका अनुपालन हुआ या नहीं हुआ।

उपसभापति: प्रश्न संख्या 184।